बजट अनुमान 2018–19 में योजनावार प्रावधान

(आंकड़े हजार रूपयों में

योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान
573	उच्च न्यायालय (भारित)	66,72,70
1912	दण्ड न्यायालय	73,00
2407	निर्वाचन	12,00,00
2409	निर्वाचन अधिकारी	20,87,80
2410	निर्वाह पत्र तामिल स्थापना	20,24,90
2449	न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	12,43,00
2450	न्याय प्रशासन	25,35,65
2918	बार एसोसिएशन के पुस्तकालयों के लिए आर्थिक सहायता	1,50,00
3255	विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	16,95,80
3307	मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	29,06,00
3428	महाधिवक्ता	11,87,60
3572	मुफस्सिल स्थापना	9,82,30
4006	राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	112,00,00
4311	संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	2,26,10
4497	सामान्य स्थापना	189,93,00
5136	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	1,00,00
5171	विशेष न्यायालयो की स्थापना	6,27,90
5416	परिवार न्यायालय की स्थापना	24,03,30
5421	छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी	10,83,75
5464	हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	8,10,00
5640	उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण	14,00,00
6222	न्याय प्रशासन के आवासगृह का निर्माण	20,00,00
7256	न्यायालयो का कम्प्यूटरीकरण	8,24,00
7502	सी.बी.आई. न्यायालय की स्थापना	87,20
7798	कॉमर्शियल कोर्ट	1,71,80
8998	भारतीय विधि संस्थान	10,00
9056	माध्यस्थम अधिकरण	2,13,50
9057	विधि एवं विधायी कार्य	9,55,70
9503	मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना	2,50,00
	योग	641,15,00